संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) तक. छठी पंच वर्षीय (1980–85) की अवधि के लिए राष्ट्रीय डाक योजना तैयार की गई है और इस समय योजना आयोग के साथ उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। परामर्श करके योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् डाक सर्किलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। तथापि योजना के अन्तर्गत विकासात्मक उपाय के बतौर ग्रामीण क्षेत्रों में केवल विभागेतर शाखा डाकघर ही खोले जाते है। अन्य डाकघर तब खोले जाते हैं जब वे अपना खर्चा स्वयं उठाने में समर्थ होते हैं।

Persons Employed under Food for Work Programme and daily Payment of Foodgrains

977. SHRI JITENDRA PRASAD: Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTON be pleased to state:

(a) the number of persons throughout the country out of total rural population who got employment under the food for work programme during 1979 and 1980 (till October, 1980) Statewise; and

(b) the daily quantity of foodgrains given to the workers in lieu of wages and total quantity alongwith cost distributed as such during 1979 and 1980 State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI BALESHWAR RAM): (a) According to information received upto-date employment generated under the Food for Work Programme (now National Rural Employment Programme) during the year 1978-79 was around 36 crores mandays and during 1979-80 around 50 crores mandays (complete information from all the States/Union Territories is yet to be received). A copy of the statement (No. I) is laid on the table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1419/80].

(b) Under the Food for Work Programme, the State Governments/ Union Territories were permitted to pay the wages of the workers engaged on works under the programme either partly or wholly in foodgrains. While some of the States/ Union Territories paid only part of the wages in foodgrains, some other paid the entire wages in foodgrains. Also the rates of wages all over the country are not uniform. Now, under the NREP, the payment of wages in foodgrains has been restricted to 3 kgs. (2 kgs. in foodgrains and price equivalent of 1 kg. in cash). During the year 1979-80, the total quantity of foodgrains allocated under FWP was about 30 lakh Metric Tonnes costing nearly Rs. 420 crore. This includes alocations under the special F.F.W. programme for the drought affected areas also. Allocation of foodgrains during the current financial year is about 21 lakh Metric Tonnes costing nearly Rs. 294 crores.

Statements (No. II and III) giving State-wise allocations for 1979-80 and 1980-81 are placed on the table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1419/80].

हिमाचल प्रदेश में सेवों के विपणन और परिक्षण के लिये विश्व बैंक की परियोजना

978. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश में सेवों के विपणन और परिरक्षण के लिए विश्व बैंक बोर्ड परियोजना चला रहा है ;

(ख) परियोजना का कुल अनुमानित व्यय कितना होगा और अब तक विभिन्न परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की

गई है अथवा विभिन्न क्षेत्रों में निकट भविष्य में कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(ग) क्या रोहड़ तहसील के लिए अभिप्रेत योजनाओ के लिए धनराशि कुछ अन्य क्षेत्रो में खर्च की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) . (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को आबंटित खाद्यान

979. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** . क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को वर्ष 1980–81 के दौरान खाद्यान्न की कितनी मात्रा आबंटित की गई थी और 1981–82 के दौरान कितनी मात्रा आवंटित किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) · राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को वर्ष 1980–81 के दौरान कुल 2,28,500 मीटरी टन खाद्यान्न अर्थात् सामान्य घटक के अन्तर्गत 54,500 मीटरी टन तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रो के लिए विशेष घटक के अन्तर्गत 1,74,000 मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किए गए है । वर्ष 1981–82 के दौरान राज्य को आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्नो की मात्रा उस वर्ष के शुरू मे निर्धारित की जाएगी ।

श्री गंगानगर और बीकानेर टेलीफोन केन्द्र का स्वचालित टेलीफोन केन्द्र मे परिवर्तन

980. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीगंगानगर टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में न बदले जाने के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : श्री गंगानगर उन लगभग 1300 स्थानो मे से एक है जहां करचल एक्सचेंजो द्वारा सेवा प्रदान की जाती है ।

देश मे स्वचल स्विचिग उपस्कर के सीमित उत्पादन के कारण इन एक्सचेंजो को स्वचल एक्सचेंज मे परिवर्तित करने की योजना तैयार करना संभव नही हो सका है ।

देशी उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय किए जा रहे है ।

Fall in Population of Cows and Buffaloes

981. SHRI MANPHOOL SINGH CHAUDHRY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of cows and buffaloes both in the rural and urban areas of the country had significantly decreased;

(b) the number of adult cows and adult buffaloes in the country, State-wise and the percentage of decrease in their number during the last three years; and

(c) the reasons for dwindling population of these animals and steps suggested to check it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a)